



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 4 नवम्बर, 2000/13 कार्तिक, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

शिमला, 4 नवम्बर, 2000

संख्या रा० नि० आ०-5-17/94-1686.—हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचनों को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं शान्तिप्रिय रूप से करवाने हेतु समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के मार्गदर्शन तथा अनुपालन हेतु एक आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) बनाना उपयुक्त, वांछनीय तथा आवश्यक समझा गया है ;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-के तथा 243-जैड ए, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के द्वारा इसमें निहित शक्तियों तथा इसे ऐसा करने हेतु प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों

का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आदर्श आचार संहिता नामतः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका एवं पंचायत आदर्श आचार संहिता, 2000 निमित्त तथा जारी करता है :—

1. नाम तथा प्रारम्भ :

1.1 (क) इसी संहिता का नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका तथा पंचायत आदर्श आचार संहिता, 2000 है।

(ख) यह संहिता प्रदेश में नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के समस्त निर्वाचनों पर लागू होगी।

1.2 यह संहिता, जब तक कि आयोग अन्यथा निर्दिष्ट न करे, उस दिन से प्रभावी तथा लागू मानी जाएगी जिस दिन आयोग प्रैम नोट अथवा सार्वजनिक वक्तव्य से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है;

परन्तु आयोग अपने विवेकानुसार संहिता के विभिन्न अनुच्छेदों को विभिन्न क्षेत्रों में या भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न तारीखों से प्रभावी तथा लागू कर सकता है।

1.3 यह संहिता या इसका कोई भी अनुच्छेद जो एक बार प्रभावी तथा लागू हो गया हो, वह निर्वाचन प्रक्रिया के समापन तक प्रभावी तथा लागू रहेगा।

2. परिभाषाएं :

2.1 यदि सन्दर्भ विशेष से प्रतिकूल अभिप्राय न झलकता हो तो निम्नलिखित शब्दों तथा वाक्यांशों का अवोलिखित अर्थ होगा :—

(क) “अभ्यर्थी” से नगरपालिका या पंचायत के निर्वाचन में अभ्यर्थी (candidate) अभिप्रेत है ;

(ख) “अध्यक्ष” से सरकार द्वारा स्वामित्व अधिकांशतः प्राप्त अथवा नियन्त्रित, नियमित, कम्पनी अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) “संहिता” से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका तथा पंचायत आदर्श आचार संहिता 2000 अभिप्रेत है ;

(घ) “आयोग” से राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(ङ) “जिला निर्वाचन अधिकारी” से वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे नगरपालिकाओं या पंचायतों के निर्वाचन सम्बन्धी जैसी भी स्थिति हो (as the case may be) कर्तव्यों का पालन करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो ;

(च) “निर्वाचन कर्मचारी” से जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटनिंग अधिकारी, सहायक रिटनिंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी, अभिप्रेत है ;

(छ) “सरकार” से हिमाचल प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) “मन्त्री” से प्रदेश के मन्त्री, जिसमें मुख्य मन्त्री, राज्य मन्त्री या उप-मन्त्री अभिप्रेत है ;

(झ) “नगरपालिका” से नगर पंचायत या नगर परिषद् जैसी भी स्थिति हो (as the case may be) अभिप्रेत है ;

- (ज) "पदाधिकारी" (से नगरपालिकाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उप-प्रधान, पंचायत अथवा जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका या पंचायत के सदस्य अभिप्रेत है;)
- (ट) "पंचायत" से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be) अभिप्रेत है;
- (ठ) "संसदीय सचिव" से राज्य का संसदीय सचिव अभिप्रेत है तथा इसमें मुख्य संसदीय सचिव सम्मिलित है ;
- (ड) "दल" से ऐसा समूह या व्यक्तियों का संगठन जो (चाहे वह पंजीकृत हो अथवा नहीं) अभ्यर्थी का समर्थन कर रहा हो या अभ्यर्थी खड़ा कर रहा हो, अभिप्रेत है ;
- (ढ) "मतदान अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे नगरपालिका या पंचायत के निर्वाचन करवाने या इस हेतु सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;
- (ण) "पीठासीन अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे नगरपालिका या पंचायत के निर्वाचन हेतु पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो ;
- (त) "लोक सेवक" में सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका या पंचायत अथवा निगमित निकाय (Body Corporate) का कर्मचारी जो सरकार के अधिकांशतः नियन्त्रण या स्वामित्व में हो, सम्मिलित हैं ;
- (थ) "रिटनिंग अधिकारी" से वह अधिकारी या कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे नगरपालिका या पंचायत निर्वाचन यथास्थिति के लिए रिटनिंग अधिकारी के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया हो तथा इसमें सहायक रिटनिंग अधिकारी भी समाहित हैं जबकि वे नगरपालिका या पंचायत निर्वाचन हेतु रिटनिंग अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों; तथा
- (द) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ।

3. सामान्य आचरण

3.1 किसी भी दल या अभ्यर्थी को कोई भी ऐसा कृत्य (activity) नहीं करना चाहिए जो किसी धर्म, मूलवंश, जाति, मत, समुदाय, भाषा, निवास या लिंग के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच विचार वैषम्य को और बढ़ाए या उनमें विद्वेष या तनाव उत्पन्न करे ।

3.2 किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने लिए मत प्राप्त करने के लिए अथवा किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को मत न देने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील नहीं की जानी चाहिए ।

3.3 उपासना स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजा-घर इत्यादि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

3.4 किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका सम्बन्ध उसके सार्वजनिक जीवन के क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जो अप्रमाणित तथ्यों या घटनाओं पर आधारित हों। दूसरे शब्दों में यद्यपि अभ्यर्थी की राजनैतिक विचारधारा की उचित आलोचना तथा उसके सार्वजनिक आचरण की निंदा की अनुमति तो होगी परन्तु ऐसे तथ्यों के वक्तव्यों से बचा जाए जिनसे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा ग्राम जनता के बीच कम हो ।

3.5 जब किसी राजनैतिक दल की आलोचना की जाए तो वह केवल उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों, पूर्व इतिहास और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा अप्रमाणित आरोपों पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

3.6 किसी भी परिस्थिति में किन्हीं व्यक्तियों की विचाराधारा या क्रियाकलापों का विरोध करने के उद्देश्य से उनके घर के बाहर प्रदर्शन करना, घेराव करना या आवश्यकता से अधिक समय तक बार-बार नारे लगाने जैसा क्रुत्य (activity) का सहारा नहीं लिया जाएगा।

3.7 समस्त दलों तथा अभ्यर्थियों को ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, के सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण (corrupt practice) और निर्वाचन अपराध (electoral offence) माने गए हैं अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्ट आचरण में ये समाविष्ट हैं :—

- (क) रिश्वत लेने या देने का कार्य ;
- (ख) अनुचित प्रभाव डालना ;
- (ग) धर्म, मूलवंश, जाति, सम्प्रदाय भाषा के आधार पर अपील करना ;
- (घ) नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, सम्प्रदाय या भाषा के आधार पर विद्वेष या शत्रुता पैदा करना या बढ़ाना ;
- (ङ) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए मुक्त वाहन का प्रबन्ध करना ;
- (च) केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय मन्त्रालयों के कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करना।

“भ्रष्ट आचरण” प्रमाणित होने पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

3.8 कोई भी दल या अभ्यर्थी अपने सदस्यों, समर्थकों अथवा अनुयायियों को किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति पर झण्डे लगाने, सूचना-पत्र/पोस्टर चिपकाने या नारे लिखने अथवा पताकाएं लटकाने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि सम्पत्ति के मालिक, प्रबन्धक या काबिज व्यक्ति की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए।

3.9 किसी भी अभ्यर्थी या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरे अभ्यर्थी द्वारा लगाए गए झण्डों या इशतहारों को हटाया अथवा विरूपित (deface) नहीं किया जाना चाहिए।

3.10 किसी भी अभ्यर्थी या दल को प्रदर्शन के दौरान अपने समर्थकों का या कार्यकर्ताओं को किसी दूसरे अभ्यर्थी या किसी दल के नेता अथवा किसी प्रमुख व्यक्ति का पुतला लेकर चलने या उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर जलान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3.11 कोई भी दल या अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। लाउडस्पीकर केवल 7.00 बजे प्रातः से 9.00 बजे माय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय में ही प्रयोग में लाया जा सकेगा।

4. बैठकें :

4.1 किसी भी अभ्यर्थी या दल द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के सूचित किए बिना अथवा, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिए बिना, कोई भी सार्वजनिक सभा या रैली या प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी या दल को यह पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सम्बन्धित क्षेत्र में कोई निषेधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किन्हीं दो अभ्यर्थियों या दलों के प्रदर्शन का आपस में टकराव न हों।

4.2 किसी प्रतिद्वन्द्वी (rival) अभ्यर्थी या दल की निर्वाचन सभा या प्रदर्शन में किसी दूसरे अभ्यर्थी या दल अथवा इसके समर्थकों या कार्यकर्ताओं द्वारा बाधा नहीं पहुँचाई जानी चाहिए।

4.3 प्रत्येक अभ्यर्थी तथा दल को शान्तिपूर्वक व्यवस्थित निर्वाचन करवाने के लिए निर्वाचन कर्मचारियों तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियुक्त कर्मियों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि निर्वाचन से पूर्व, निर्वाचन के समय तथा निर्वाचन के बाद उचित वातावरण बना रहे।

4.4 किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वाचन सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न अभ्यर्थियों या दलों में भेदभाव न किया जाए। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक अभ्यर्थी या दल एक ही जगह पर सभा करने की अनुमति मांगें तो उस अभ्यर्थी या दल को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया हो। अन्य अभ्यर्थियों या दलों को सभा की अनुमति उसी क्रम में दी जाए जिस क्रम में उन्होंने आवेदन दिए हैं तथा उन्हें किसी अन्य स्थल या समय पर सभा करने का परामर्श दिया जाना चाहिए।

4.5 सामान्यतः निर्वाचनों के दौरान आयोजित की जाने वाली सभी सभायें निर्वाचन सभायें मानी जाएंगी तथा उन पर कोई भी सरकारी पैसा व्यय न किया जाए।

5. निर्वाचन व्यय :

5.1 कोई भी अभ्यर्थी, निर्वाचन हेतु निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगा।

5.2 जिन अभ्यर्थियों पर संहिता का अनुच्छेद 5.1 लागू होता है वे निर्धारित फार्म पर प्रतिदिन के व्यय का लखा रखेंगे।

5.3 ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय का सही लेखा निर्धारित फार्म पर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

6. सरकारी तन्त्र :

6.1 (क) सरकारी कर्मियों को निर्वाचन के दौरान पूर्णतः निष्पक्ष रहना चाहिए।

(ख) उन्हें किसी भी प्रकार का प्रचार अथवा किसी भी अभ्यर्थी या दल के पक्ष अथवा विपक्ष में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।

6.2 कोई भी सरकारी कर्मकारी किसी निर्वाचन सभा का आयोजन, सम्बोधन, वित्तीय प्रायोजन नहीं करेगा और न उसमें सक्रिय भाग लेगा। यह प्रावधान सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त कर्मियों तथा सार्वजनिक व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था हेतु नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

6.3 यदि निर्वाचन दौरे के समय कोई मन्त्री/संसदीय सचिव/अध्यक्ष किसी निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का निमन्त्रण स्वीकार कर ले तो सरकारी कर्मचारियों को उस के साथ उसमें नहीं जाना अथवा उसमें शामिल नहीं होना चाहिए।

6.4 विश्रामगृहों, विश्राम भवनों (Circuit Houses) तथा अन्य सरकारी आवास सुविधा का उपयोग सभी अभ्यर्थियों तथा दलों को उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है। सामान्यतः इनके उपयोग की अनुमति अल्प अवधि के लिए तथा पहले-आए-पहले-पाए के आधार पर ही दी जानी चाहिए तथा किसी को भी इस सुविधा पर एकाधिकार की

अनुमति न दी जाए। किसी भी अभ्यर्थी या दल को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

7. सत्ताधारी दल हेतु :

7.1 यदि कोई मंत्री/संसदीय सचिव/अध्यक्ष निर्वाचन के दौरान उस जिले का दौरा करें जहाँ निर्वाचन हो रहे हों तो ऐसा दौरा चुनाव सम्बन्धी दौरा माना जाएगा तथा उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों, कानून व्यवस्था तथा यातायात प्रबन्ध में संलग्न कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य कोई भी सरकारी कर्मचारी सम्मिलित नहीं होगा। ऐसे प्रवास हेतु कोई भी सरकारी वाहन या अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।

7.2 निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से किसी भी मंत्री/संसदीय सचिव/अध्यक्ष, संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य या अभ्यर्थी को कोई भी सरकारी या नगरपालिकाओं अथवा पंचायत या सार्वजनिक संस्थान या सहकारी सभाओं या किसी भी अन्य संस्थान, जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हों, से सम्बन्धित वाहन चुनाव प्रचार हेतु उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा।

7.3 मन्त्रियों/संसदीय सचिवों/अध्यक्ष को अपने सरकारी दौरो को चुनाव प्रचार के कार्यों से नहीं जोड़ना चाहिए और न ही सरकारी तंत्र तथा कमियों अथवा सरकारी वाहनों सहित अन्य सरकारी साधनों का उपयोग किसी अभ्यर्थी के हितों को लाभ पहुंचाने की मंशा से करना चाहिए।

7.4 निर्वाचन के दौरान समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार माध्यमों से, सरकारी खर्च पर ऐसे विज्ञापन नहीं किए जाने चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

8. लाभ पहुंचाना :

8.1 राज्य सरकार, मंत्री/संसदीय सचिव/अध्यक्ष, नगरपालिकाएं तथा पंचायतें, उनके पदाधिकारी और अन्य प्राधिकारी :—

(क) जहाँ निर्वाचन हो रहे हों उस क्षेत्र में कोई भी वित्तीय अनुदान स्वीकृत या उपलब्ध नहीं करवाएंगे;

(ख) किसी भी नई योजना का वादा, घोषणा या स्वीकृति नहीं देंगे/करेंगे;

(ग) किसी भी नई योजना अथवा परियोजना का प्रारम्भ या शिलान्यास, सड़क के निर्माण, जल आपूर्ति योजना या अन्य सार्वजनिक सुविधा का वायदा नहीं करेंगे;

(घ) किसी भी तरह की नियुक्ति (यथा तदर्थ, अनुबन्ध दैनिक वेतन भोगी) नहीं करेंगे;

(ङ) सार्वजनिक निधियों से सहायता हेतु नए लाभार्थियों का चयन नहीं करेंगे;

(च) कर्मचारियों के स्थानान्तरण या पदोन्नति नहीं करेंगे।

9. मतदान से पूर्व, दौरान तथा बाद में :—

9.1 कोई भी अभ्यर्थी अथवा दल मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व तक कोई भी प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा नहीं करेगा।

9.2 मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान-पत्रिका सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए तथा उन पर किसी अभ्यर्थी का नाम अथवा चुनाव चिन्ह (Symbol) नहीं होना चाहिए। पत्रों पर केवल मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड संख्या मतदान केन्द्र संख्या तथा निर्वाचन नामावली में उसकी क्रम संख्या ही लिखी जानी चाहिए।

9.3 किसी अभ्यर्थी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता (Authorised Agent) के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र या मतगणना केन्द्र में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए अनुमति पत्र (पास) के बिना मतदान केन्द्र या मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।

9.4 किसी भी अभ्यर्थी का शिविर, मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर स्थापित नहीं होना चाहिए। यदि कहीं एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित हों, तो ऐसे मतदान केन्द्रों समूहों के लिए भी एक अभ्यर्थी का ऐसे परिसर से 100 मीटर की दूरी के बाहर एक ही शिविर होना चाहिए।

9.5 कोई भी अभ्यर्थी (क) मतदान केन्द्र के प्रवेश-द्वार के समीप अथवा किसी निकट के सार्वजनिक या निजी स्थान पर लाउड-स्पीकर या मैग्फोन का प्रयोग नहीं करेगा, (ख) मतदान केन्द्र के अन्दर या समीप उच्छ्वस अथवा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे ड्यूटी पर तैनात मतदान अधिकारियों के कार्य में विघ्न पड़े।

9.6 कोई भी व्यक्ति शारीरिक बल अथवा अन्य किसी प्रकार के बल का प्रयोग करके किसी मतदाता को अपना मत डालने अथवा मतदान केन्द्र के अन्दर जाने से नहीं रोकेंगा या उसके ऐसा करने में बाधा नहीं डालेगा।

9.7 ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, जो निर्वाचन कर्मियों के विधेय-सम्मत निर्देशों का पालन नहीं करता, पुलिस द्वारा मतदान केन्द्र से बाहर निकाला जा सकता है।

9.8 यदि कोई व्यक्ति छल-पूर्वक या बल-पूर्वक, मतपत्रों को मतदान केन्द्र से बाहर ले जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

9.9 प्रत्येक अभ्यर्थी तथा दल शान्ति पूर्वक तथा सुव्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न करवाने हेतु निर्वाचन कर्मियों के साथ सहयोग करेंगे।

10. सहायता :

10.1 यदि अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचन के बारे में कोई शिकायत या कठिनाई हो तो वह अपनी शिकायत या रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों अथवा प्रेक्षक को, यदि आयोग द्वारा नियुक्त किया गया हो, दे सकते हैं।

10.2 यह प्रत्येक अभ्यर्थी के हित में होगा कि वह आदर्श आचार संहिता का पालन करे अन्यथा उसके निर्वाचित होने पर, किसी निर्वाचन याचिका के आधार पर, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है अथवा अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

11. उल्लंघन के परिणाम :

11.1 आदर्श आचार संहिता के अधिकतर प्रावधानों का उल्लंघन एक अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है।



12. निरसन :

आयोग द्वारा इससे पूर्व अपने पत्र सख्या : रा0 नि0 आ0-16-4/97-2087, दिनांक 5-11-1995 द्वारा निमित्त/प्रवृत्त आचार संहिता एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

आदेश द्वारा,

कृष्ण चन्द्र शर्मा,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2000

No. SEC-5-17 94-1644.—Whereas it is considered appropriate, desirable and necessary in the interest of free, fair, smooth, orderly and peaceful conduct of elections to the Municipalities and Panchayati Raj Institutions in the State of Himachal Pradesh to formulate and issue a model code of conduct for guidance of and compliance by all concerned ;

Now, therefore, in exercise of the powers vesting in it under Articles 243 K and 243 ZA of the Constitution of India, Section 281 of the **Himachal Pradesh Municipal Act, 1994** and Section 160 of the **Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994** and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission of Himachal Pradesh makes and hereby issues the following model code of conduct, namely the **Himachal Pradesh Municipalities and Panchayats Model Code of Conduct, 2000**:—

1. Title and Commencement :

1.1 (a) This Code shall be called the Himachal Pradesh Municipalities and Panchayats Model Code of Conduct, 2000.

(b) This Code shall apply to all elections to Municipalities and Panchayats in the State.

1.2 This Code shall, unless otherwise directed by the Commission, come into effect and be applicable on the date on which the Commission announces the election programme through a press note or public statement:

Provided that the Commission may in its discretion make different paragraphs of the code an effective and applicable on different dates, in different areas or in relation to different Municipalities or Panchayats.

1.3 The Code or any of its paragraphs which has become effective and applicable, shall continue to effective and applicable till the election process is completed:

2. Definitions :

- 2.1 Unless a contrary intention appears from the context, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them hereunder :
- (a) "Candidate" means a candidate for election to a Municipality or Panchayat;
 - (b) "Chairman" means a Chairman (and includes a Vice-Chairman) of a Corporation or a Company or a Board substantially owned or controlled by the Government.
 - (c) "Code" means the Himachal Pradesh Municipalities and Panchayats Model Code of Conduct, 2000;
 - (d) "Commission" means the State Election Commission of Himachal Pradesh;
 - (e) "District Election Officer" means an Officer appointed to perform the duties of "District Election Officer" in connection with the elections to a Municipality or a Panchayat, as the case may be ;
 - (f) "Election Personnel" means the District Election Officer, Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer and Polling Officers;
 - (g) "Government" means the Government of the State;
 - (h) "Minister" means a Minister of the State and includes the Chief Minister, Minister of State or Deputy Minister;
 - (i) "Municipality" means a Nagar Panchayat or a Municipal Council, as the case may be ;
 - (j) "Officer bearer" includes the President and the Vice-President of a Municipality, the Pradhan and Up-Pradhan of a Gram Panchayat or Gram Sabha, the Chairman and Vice-Chairman of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad and the Member of a Municipality or a Panchayat ;
 - (k) "Panchayat" means a Gram Panchayat, a Panchayat Samiti or a Zila Parishad, as the case may be ;
 - (l) "Parliamentary Secretary" means a Parliamentary Secretary of the State and includes a Chief Parliamentary Secretary ;
 - (m) "Party" means a group or association of persons, whether registered or not, setting up or supporting a candidate ;
 - (n) "Polling Officer" means a person appointed to conduct or to assist in the conduct of elections to a Municipality or a Panchayat ;
 - (o) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer for the conduct of election to a Municipality or a Panchayat;
 - (p) "Public Servant" includes a Government Servant and an employee of a Municipality or a Panchayat or a body corporate controlled or substantially owned by the Government;

- (q) "Returning Officer" means an Officer or Official appointed to perform the duties of a Returning Officer in connection with election to a Municipality or a Panchayat, as the case may be, and includes an Assistant Returning Officer, while discharging the duties of a Returning Officer, for conducting election to a Municipality or a Panchayat ; and
- (r) "State" means the State of Himachal Pradesh.

3. General :

- 3.1 No party or candidate shall indulge in any activity which may aggravate existing differences or tensions or create mutual hatred or cause tension between different groups of people on the basis of religion, race, caste, creed, community, language, residence or sex.
- 3.2 These shall be no appeal on the basis of religion, race, caste, community or language for securing votes for a candidate including oneself or for not voting for a particular candidate.
- 3.3 Places of worship such as temples, mosques, churches, etc. shall not be used as a forum for election propaganda.
- 3.4 No criticism of any aspect of the private life of a candidate which is not connected with his public life or activities shall be made nor any allegation shall be made which is based on unverified facts or incidents. In other words while reasonable criticism of the political ideology or public conduct of a candidate is permissible false statement or fact affecting the individual beneath the publicman should be avoided.
- 3.5 Criticism of a party, when made, shall be confined to its policies and programmes, past record and work and shall not be based on unverified allegations.
- 3.6 Organising demonstrations or picketings or repeatedly shouting slogans for more than reasonable time before the houses of individuals by way of protesting against their opinions or activities shall not be resorted to under any circumstances.
- 3.7 All parties and candidates shall avoid scrupulously all activities which are corrupt practices or electoral offences under the relevant provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act and the Himachal Pradesh Municipal Act. Corrupt practices include, *inter alia*, (a) bribery (b) undue influence, (c) appeal on the basis of religion, race, caste, community or language, (d) promoting enmity or hatred among different class of citizens on grounds of religion, race, caste, community or language, (e) arranging free conveyance for carrying voters to and fro from a polling station (g) obtaining assistance of the employees of Central or State Government or of a local body. Proof of Commission of a corrupt practice may render a candidate liable to be disqualified.
- 3.8 No party or candidate shall permit its or his members, supporters or followers to use any private or public property for erecting flag staffs, pasting notices, posters or slogans, etc. or suspending banners without permission of the owner or manager or the person in possession of the property concerned.
- 3.9 No candidate or his workers shall remove or deface the flags flown or posters pasted by another candidate or party.

- 3.10 No candidate or party shall carry or allow his or its supporters or workers to carry the effigy of another candidate or party leader or other prominent person in a procession or burn such effigy in a public place.
- 3.11 No party or candidate shall use loud speakers without obtaining necessary permission from the competent authority. The loud speakers shall be used only between 7.00 A. M. and 9.00 P. M. or such time as the competent authority might allow.

Meetings :

- 4.1 No candidate or party shall hold public meetings or rallies or take out processions without prior information to and, where necessary, with prior permission of the competent authority. He or it should ascertain in advance whether there are any prohibitory orders or traffic restrictions. It should be ensured that processions of different candidates or parties do not clash.
- 4.2 Election meetings or processions of a rival candidate or party shall not be disturbed by a candidate or party or his/its workers or supporters.
- 4.3 Every candidate and party shall co-operate with the election personnel in holding a peaceful and orderly poll and with those charged with the maintenance of law and order to ensure proper atmosphere before, during and after the poll.
- 4.4 While granting permission for organising an election meeting at a public place, no distinction should be made between different candidates or parties. In case more than one candidate or party requests for holding meetings at the same place on the same date and at the same time, the permission should be granted to such candidate or party who had applied first. Other candidates or parties may be granted permission to hold meetings in the order in which they applied in point of time and they should be persuaded to hold such meetings at other place or time.
- 4.5 Ordinarily, all meetings organised during elections should be treated as election meetings and no Government money should be spent on them.

5. Election Expenses :

- 5.1 No contesting candidate shall incur expenditure in connection with his elections in excess of the prescribed limit.
- 5.2 The contesting candidate to whom 5.1 applies, shall maintain day-to-day expenditure record in the prescribed proforma.
- 5.3 Every such candidate shall within 30 days of announcement of results submit a true account of election expenditure in the prescribed proforma to the prescribed authority.

6. Government Machinery :

- 6.1 (a) A public servant shall remain absolutely impartial during the elections.
- (b) He shall not indulge in any campaign activity or work for or against any contesting candidate or political party.

- 6.1 No public servant should organise, address, finance or take active part in any election meeting. This, however, does not preclude the discharge of official duties by those charged with the maintenance of public order and management of traffic.
- 6.2 A public servant shall not participate or accompany the Minister in any programme organised at an individual's house for which the Minister has accepted the invitation during his election tour.
- 6.3 Use of rest houses, circuit houses and other Government accommodation should be permitted to all the candidates and parties on the same terms and conditions on which it is permissible for the party in power. Those should normally be permitted to be used for short periods and on first-come-served basis without allowing anyone to monopolise the facility. However, no candidate or party should be allowed to use such building or its precincts for the purpose of election propaganda.

7. Party in Power :

- 7.1 If a Minister/Parliamentary Secretary/Chairman undertakes a tour of any area of a District where elections are taking place, such tour shall be deemed to be an election tour and no Government servant except those who are deployed for security, law and order and traffic management shall accompany the Minister/Parliamentary Secretary/Chairman. No Government vehicles or any other facility shall be made available for such tour.
- 7.2 No vehicles belonging to Government or Municipalities or Panchayat or public undertakings or co-operative societies or any other institutions receiving Government grants shall be provided to any Minister/Parliamentary Secretary/Chairman, Member of Parliament or of Legislative Assembly or a candidate for canvassing in election in any manner from the date of notification of election.
- 7.3 The Ministers/Parliamentary Secretary/Chairman shall not combine their official visit with electioneering work and shall not make use of official machinery and personnel or other Government resources including Government vehicles for furtherance of interests of any candidate.
- 7.4 Issue of advertisement at the cost of the public exchequer in newspapers and other media during the election period for partisan coverage intended to further the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided.

8. Granting or Providing Benefits :

- 8.1 The State Government, Minister/Parliamentary Secretary/Chairman, Municipalities and Panchayats, their office-bearers and other authorities:—
 - (a) shall not sanction or provide any financial grants in any area where the elections are to take place;
 - (b) shall not sanction or announce or promise any new scheme;
 - (c) shall not lay foundation stones of or open any new scheme or project or promise construction of any road, water supply scheme or other such public facility;

- (d) shall not make any appointment of any nature including *ad hoc*, contract, daily rated, appointment ;
- (e) shall not select new beneficiaries for assistance from public funds; and
- (f) Promote or transfer personnel.

9. Before, during and after the Poll :

- 9.1 No candidate or party shall hold public meetings or takeout processions during the period of 48 hours ending with the hour fixed for the close of the poll.
- 9.2 The identity slips given to voters shall be on plain (white) paper and shall not contain any symbol or name of the candidate. Only name of the voter, his father's or her husband's name, ward number, polling booth number and the serial number of the voter in the electoral roll shall be written on the identity slip.
- 9.3 No one shall enter any polling station or place of counting without a pass issued by the District Election Officer or Returning Officer except in his capacity as a candidate or a voter intending to constitute or an authorised agent.
- 9.4 No candidate's camp shall be set up within a distance of 100 meters from the polling station. Even where more than one polling stations has been set up in the same premises, there shall be only one such camp of a candidate for such group of polling stations beyond a distance of 100 metres from such premises.
- 9.5 No person shall (a) use or operate within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighbourhood a megaphone or a loud-speaker ; (b) act in a disorderly manner in or near the polling station so as to interfere with the work of the Polling Officers on duty.
- 9.6 No one will obstruct or prevent, by using physical force or otherwise, a voter from entering a polling station or casting his vote.
- 9.7 Any person who fails to obey the lawful directions of the Election Personnel shall be liable to be removed from the polling station by the police.
- 9.8 Any person who fraudulently or forcibly takes or a ballot paper out of the polling station will be liable to be proceeded against.
- 9.9 Every candidate and party shall co-operate with the Election Personnel to ensure peaceful and orderly polling.

10. Assistance :

- 10.1 Candidates or their election agents may, when necessary give specific complaint or report difficulties regarding the conduct of elections to the District Election Officer, the Returning Officer or to the Observer, if appointed by the Commission.
- 10.2 It would in the interest of the candidate to ensure compliance with the Code otherwise he may, if elected, render himself liable to be disqualified or be inelected on an election petition.

11. Consequence of Violation :

- 11.1 The violation of most of these provisions constitutes an offence which may render the person violating these liable to be prosecuted in a court of law.

12. Repeal :

- 12.1 The Code of Conduct earlier formulated and circulated vide this Commission's letter No. SEC.16-4/95-2087, dated 5-11-1995 is hereby repealed.

By order,
K. C. SHARMA,
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 4th November, 2000

No. SEC-5-17/94-I-1687-2059.—In exercise of the powers vested in it under Article 243-K and 243 ZA of Constitution of India, Section 281 of the H.P. Municipal Act, 1994 and Section 160 of the H. P. Panchayati Raj Act, 1994 and para 1.2 of the H. P. Municipal and Panchayat Elections Model Code of Conduct 2000, the State Election Commission of Himachal Pradesh, hereby directs that the aforesaid Code shall come into force in the State of Himachal Pradesh (barring the Sub-division of Keylong & Udaipur in District Lahaul-Spiti and Pangi Sub-division of District Chamba and territorial area of Municipal Corporation, Shimla) with effect from 16th November, 2000.

By order,
(K. C. SHARMA),
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

Copy to the Chief Secretary Government of Himachal Pradesh with the request that strict adherence and compliance of the Code may please be ensured,

Sd/-
(PURNIMA CHAUHAN)
Secretary,
State Election Commission,
Himachal Pradesh.